चाहता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण धरोहरों को अपने देश में वापस लाने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ गंभीरता से बातचीत की जाए जिससे अपने देश के ये दो जो गौरव हैं, वापस आ सकें।

जैसा कि सर्वविदित है कि कोहिनूर हीरा सन् 1839 में महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र महाराजा दलीप सिंह की हार के बाद लाहौर समझौता संधि के रूप में महारानी विक्टोरिया को समर्पित कर दिया गया था और इंग्लैंड ले जाया गया था। आज़ादी के बाद इसे भारत में वापस लाने के लिए ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया गया परन्तु कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराजा की भवानी तलवार को वापस लाने के लिए श्री अन्तुले जी के मुख्यमंत्रित्व काल में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाया गया था। यह धरोहर भी ब्रिटिश सरकार के पास है और ऐतिहासिक है। यह न केवल महाराष्ट्र की, अपितु पूरे भारत की शान का सवाल है। मेरे विचार से इन रत्नों को वापस लाने में सरकार गंभीर दिखाई नहीं देती और हमारी approach इस मामले में बड़ी casual सी रही है। जब-जब यह मामला उनके साथ उठाया गया, तब-तब ब्रिटिश सरकार ने अपने Museum Act 1963 का हवाला देते हुए इस धरोहर को वापस करने से यह कहते हुए मना कर दिया कि इस हीरे को वैद्य तरीके से अधिगृहित किया गया था इसलिए उनके National Museum से ऐसी ऐतिहासिक और कीमती धरोहर नहीं हटाई जा सकती। इस बात को ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की भारत यात्रा में भी दोहराया है। परन्तु बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि कोहिनूर के मामले में ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने जिस प्रकार का बयान देकर सारी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है, इस संदर्भ में मेरा कहना यह है कि उसी आवाज में हमें अपने अधिकार की बात को उनको वापस दोहराना चाहिए और तब तक चुप नहीं रहना चाहिए, जब तक ये दोनों धरोहर हमारे पास वापस भारत में न आ जाएं।

Demand to take steps for revival of Railway Wagon Factories at Mocama and Muzaffarpur in Bihar and revise salaries of their workers

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : बिहार औद्योगिक दृष्टि से अति पिछड़ा प्रदेश है। भारत वैगन की दो इकाई मोकामा एवं मुजफ्फरपुर में अंग्रेजों के ज़माने से बटलर का कारखाना के रूप में कार्य कर रही थी। रेलवे वैगन का उत्पादन करने के बावजूद पिछली सरकारों की आर्थिक नीतियों के कारण वे कारखाने बन्दी के कागार पर पहुंच गए। किन्तु इन कारखानों के कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए वैगनों की भारतीय रेल में उपयोगिता समझ पूर्व रेल मंत्री ने बिहार की दोनों इकाईयों को रेल विभाग के अधीन 13-08-2008 को कर लिया। किन्तु वर्तमान में बिहार के

दोनों कारखाने एवं उसमें कार्यरत हजारों कर्मचारी लगातार उपेक्षा का पात्र बने हुए हैं। समय पर वैगन उत्पादन का आर्डर प्राप्त न होना, उत्पादन के लिए आवश्यक है मैटीरियल की आपूर्ति न होना आम बात है। किन्तु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पूरे भारत में छठवें वेतनमान का हल्ला हो रहा है, हर राज्य में कर्मचारियों को वह देर सवेर मिल रहा है जबकि इन कारखानों के हजारों कर्मचारी आज भी पांच हजार रुपए मात्र के वेतन पर काम कर रहे हैं। तीन वेतन पुनरीक्षण 1-1-1997, 1-1-2002 और 1-1-2007 लम्बित है। कारखाने के प्रबंधक कर्मचारियों के तमाम बकाया एवं 5 माह के वेतन को निबटाने में अक्षम हैं। प्रबंधक ने यूनियन के साथ वेतन का 35 प्रतिशत बढ़ाकर अप्रैल, 2009 के वेतन में देने का समझौता किया था, किन्तु अब तक कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला है। सुना है कि कम्पनी के लिए कोई रिवाइवल पैकेज का प्रस्ताव रेल विभाग में है। किन्तु इस महंगाई की मार से पीड़ित बिहार के इन कर्मचारियों को बचाने के लिए गुजारिश है कि सरकार बिहार के प्रति अपनी नीति बदलकर शीघ्र निर्णय करे और इन कारखानों का पुनरुद्धार करे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at twenty-seven minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at twenty seven minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The LOP wanted five minutes.

SHORT DURATION DISCUSSION

Recent Development relating to Bhopal Gas Tragedy

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I am extremely grateful to you that even though the debate had finally concluded, for a very brief intervention arising out or what happened yesterday, you have been gracious enough to permit me a few minutes. One of the